नीदरलैंड्स के एक युवक को हाल ही में हाई मिडिल एजेज़ (1000 से 1300 ईस्वी) के दुर्लभ आभूषणों का एक जखीरा मिला है। पेशेवर इतिहासकार, 27 वर्षीय युवक लॉरेन्ज़ो रुज्टर दस साल की उम्र से मैटल डिटैक्टिव है। लॉरेन्ज़ो ने कहा, वर्ष 2021 में हुगवाउड में मिले इस खजाने को 2 साल तक गुप्त रखना मुश्किल था। दो साल तक नैशनल म्यूज़ियम ऑफ एन्टिक्विटीज़ में इसकी सफाई, जांच व पहचान की गई। खजाने में चार अलंकृत गोल्ड पैन्डैंट, अर्द्ध चन्द्राकार कान की बालियाँ, स्वर्ण निर्मित दो पत्तियाँ और चांदी के 39 सिक्के हैं। यह सामान 1000-1250 ईस्वी के बीच का है। म्यूज़ियम ने बताया कि, चांदी के सिक्कों से पता चलता है कि, खजाना कब दबाया गया होगा, संभवतया सन् 1248 के तुरंत बाद। सिक्कों के साथ कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं। संभवतया सिक्के कपड़े में लपेटे गए होंगे या कपड़े की पोटली में रखे होंगे। ये सिक्के डायोसीज़ ऑफ यूट्रैक्ट, विभिन्न काउन्टीज़ (हॉलैण्ड आदि) और जर्मन साम्राज्य के हैं। इनमें जो सबसे नए सिक्के हैं वो सन् 1247 या 1248 में, होली रोमन एम्पायर के सम्राट विलियम द्वितीय के समय में ढाले गए थे। आभूषण हालांकि 200 साल ही पुराने हैं, पर म्यूज़ियम का मत है कि, किसी के लिए यह बहुत कीमती खजाना रहा होगा। नॉर्दर्न यूरोप में चांदी की खानें तो बहुत थीं पर सोना दुर्लभ था। जब यह खजाना ज़मीन में गाड़ा गया होगा तब वैस्ट फ्राइसलैण्ड और हॉलैण्ड काउण्टी में गृह युद्ध चल रहा था और हुगवाउड इसका केन्द्र था। वॉर के दौरान डच काउण्ट और नैशनल हस्ती विलैम द्वितीय की मौत भी यहीं हुई थी, इसलिए यह खजाना और भी महत्वपूर्ण है।

तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय गिरफ्तार हुये

बंडी संजय पर 10वीं कक्षा की हिन्दी का पेपर लीक करने में कथित रूप से संलिप्त होने का आरोप है

- **बंडी संजय के खिलाफ मामला करीमनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन में और वारंगल के कमलापुर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है।**
- **एफ.आई.आर. के अनुसार, संजय को सुरक्षात्मक उपायों के रूप से गिरफ्तार किया गया है जिससे छात्रों की परीक्षाएं बाधित न हो सके।**
- **भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को पूरे राज्य में धरना-प्रदर्शन किया।**

करीमनगर 5 अप्रैल (वार्ता) । भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को मंगलवार आधी रात 10वीं कक्षा का हिन्दी प्रश्न पत्र लीक करने में कथित रूप से संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राज्य में एसएससी की परीक्षाएं तीन अप्रैल से शुरू हुई है।

प्राथमिकी के अनुसार, बंदी संजय कुमार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 154 और 157 के अंतर्गत दो मामला दर्ज किया गया है।

उनके खिलाफ मामला करीमनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन में और वारंगल के कमलापुर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, संजय को सुरक्षात्मक उपायों के रूप से गिरफ्तार किया गया है जिससे छात्रों की परीक्षाएं बाधित न हो सके।

पुलिस ने प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि संजय ने विकाराबाद और कमलापुर में प्रश्न पत्र लीक (तेलुगु और हिंदी) पर एक प्रेस विज्ञिप्त जारी की थी।

इसमें यह भी कहा गया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के व्यवहार से शांति और सुरक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा उन्होंने पार्टी नेताओं से परीक्षा केंद्रों पर धरना देने का आ ान किया।

एसीपी थुला श्रीनिवास के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने संजय को कल आधी रात 0045 बजे गिरफ्तार किया, जब वह 9वें दिन के समारोह में शामिल होने के लिए अपनी सास के घर पर थे। उन्हें यादाद्री भुवनगिरी जिले के बोम्मलरामाराम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया दिया।

भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को पूरे राज्य में धरना-प्रदर्शन किया।

तेलंगाना भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता एन वी सुभाष ने बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। सुभाष ने सवाल किया कि क्या राज्य में कोई लोकतंत्र है? उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा आधी रात में गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। उन्होंने अपने बयान में कहा, उन्होंने बिना कोई कारण बताये हमारे पार्टी प्रमुख को जबरन उठा लिया और यहां तक कि करीमनगर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए एक जनप्रतिनिधि का भी सम्मान नहीं किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव अमानवीय हैं और संजय को अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि वह सत्ता के नशे में चूर हैं। भाजपा प्रवक्ता ने अपने पार्टी प्रमुख की तत्काल रिहाई की मांग की।

संजय अपनी सास के निधन के बाद नौवें दिन के रीति-रिवाज में शामिल होने के लिए करीमनगर पहुंचे थे। यहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

'सुरक्षा खतरे का हवाला देकर आलोचना करने वाले चैनल को बेवजह बंद नहीं किया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध के केन्द्रीय सरकार के आदेश को खारिज करते हुये यह टिप्पणी की

- **राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला का हवाला देकर केन्द्र सरकार ने चैनल ''मीडिया वन'' का प्रसारण रोक दिया था।**
- **कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सत्ता के सामने सच बोलना प्रेस का कर्तव्य है।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ''एक लोकतांत्रिक गणराज्य के मजबूत कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मीडिया का कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले।**

नई दिल्ली 5 अप्रैल (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर प्रसारण नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाला केंद्र सरकार का फैसला बुधवार को रद्द करते हुए कहा कि सत्ता के सामने सच बोलना प्रेस का कर्तव्य है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड, और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मीडिया वन पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के आदेश पर मुहर लगाने वाले केरल उच्च न्यायालय का फैसला पलटते हुए कहा कि प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता से सच बोले और नागरिकों को तथ्यों के बारे में सूचित करे।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर मीडिया पर प्रतिबंध प्रचलित कानून के खिलाफ है। पीठ ने मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की आलोचना का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह (मीडिया संस्थान) सरकार के खिलाफ है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सामाजिक-आर्थिक से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरे से संबंधित तथ्यों को बिना ठोस सबूत के स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पीठ ने अपने फैसले में कहा, "एक लोकतांत्रिक गणराज्य के मजबूत कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालती है। मीडिया का कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले।..."

शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपनायी गई सीलबंद कवर कार्यवाही की भी आलोचना करते हुए कहा, "सभी जांच रिपोर्टों को गुप्त नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं।" शीर्ष अदालत ने 15 मार्च 2022 को मलयालम टीवी न्यूज चैनल पर केंद्र के 31 जनवरी 2022 के प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी।

केरल उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसारण पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने के बाद मीडिया वन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

मीडिया वन का प्रसारण 31 जनवरी 2022 को बंद किए जाने के बाद इस मीडिया संस्थान ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की याचिका खारिज की

- **विपक्षी दलों ने सरकार पर सी.बी.आई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुये यह याचिका दायर की थी।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राजनेताओं को कोई विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ है, बिना किसी प्रमाण के इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते।**
- **सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं की ने अपनी याचिकाएं वापस लेने की गुजारिश की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।**

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाली 14 विपक्षी दलों की याचिकायें बुधवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जी. बी. पारदीवाला की पीठ ने कांग्रेस एवं अन्य दलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में राजनीतिक दलों को आम नागरिकों की अपेक्षा कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है।

शीर्ष अदालत की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिकाएं वापस लेने की गुजारिश की थीं, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

याचिका में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि सीबीआई और ईडी ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए रही है। विपक्षी दलों को चुनचुन का निशाना बनाया जा रहा है।

साथ ही, इससे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

याचिका दायर करने वालों दलों में कांग्रेस पार्टी के अलावा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), शिवसेना (उधव ठाकरे), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी (एसपी), जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि शामिल हैं।

कर्नाटक के मु.मंत्री ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से संबंधित कई अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें महारत हासिल हैं।

किचा सुदीप बिग बॉस कन्नड़ होस्ट हैं तथा उनके पास कई बड़ी फिल्मों की लाइन लगी हुई है। एक भीड़ भरी प्रैस कॉन्फ्रैंस में, मुस्कुराते हुए बोम्मई के पास बैठे किचा ने घोषणा की कि वे भाजपा का प्रचार करेंगे तथा यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा उम्मीदवारों का प्रचार करने का उनका यह निर्णय कोई राजनैतिक निर्णय नहीं है।

उन्होंने कहा, "यह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत निर्णय है। यह निर्णय बोम्मई के सहयोग के लिये मेरे परिवार द्वारा दी गई सलाह के कारण लिया गया है।" किचा ने आगे कहा, "अंकल बोम्मई, जिन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी की, खातिर, मैं अंकल बोम्मई की इच्छा के अनुरूप कहीं भी, किसी भी (प्रत्याशी का) प्रचार करूँगा।" दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा सुपर स्टार, जो मुख्यमंत्री को "अंकल" कहता है तथा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, भाजपा में शामिल नहीं हुआ है, जबकि उसके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन इस निर्णय की वस्तुस्थिति वही व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, जो इस संदर्भ से परिचित हो कि किचा के मित्र हैं जो राजनैतिक परिदृश्य मे जाने के बाद, उससे निकल आये है तथा संभवत: इसीलिये किचा ने एक सीमित भूमिका के लिये ही सहमति दी है।

किचा ने इस प्रकार के तमाम प्रश्नों के उत्तर में कहा, "नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा तथा किसी भी राजनैतिक दल में शामिल नहीं होऊँगा। मैं फिल्मों में खुश हूँ और मैं फिल्में ही करता रहूँगा।"

जहाँ तक बोम्मई, जिन पर कांग्रेस की ओर से तथा भाजपा के अंदर से भी हमले हो रहे हैं, का प्रश्न है, कन्नड फिल्म जगत के सबसे बड़े सुपर स्टार को अपने साथ लेने की आज की सफलता से एक ऐसे राज्य में उनकी ताकत सामने आ गई है, जहाँ उनकी पार्टी के बड़े-बड़े नेता जनता से जुड़े हुये हैं, जबकि उनकी स्वयं की जन नेता की छवि नहीं है।

अब, सुपर स्टार किचा, जो नायक समुदाय (अनुसूचित जाति) से हैं, के साथ आ जाने से बोम्मई ऐसी आशा बाँध सकते हैं कि अनुसूचित जाति, बहुल क्षेत्र, खासतौर से हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में स्थिति बदली जा सकती है। यह तो निश्चित है कि सुपर स्टार किचा के प्रचारक के रूप में आ जाने से भाजपा को प्रचार के मामले मे एक बड़ा हथियार मिल गया है।

भाजपा नेताओं को अब यह उम्मीद हो गई है कि इस स्टार पावर से पार्टी को पर्याप्त बल मिलेगा तथा कांग्रेस द्वारा बोम्मई सरकार पर लगाई गई भ्रष्टाचार की कालिख से लोगों का ध्यान हट जायेगा।

बोम्मई सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के नारे- "40 प्रतिशत कमीशन सरकार" तथा "पेसीएम" जनता में बहुत लोकप्रिय हो गये हैं तथा इनके चलते बोम्मई कुछ-कुछ बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। वे इन चुनावों, जिनके लिये उन्हें भाजपा द्वारा अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, के रास्ते फिर से सत्तासीन होने के प्रयास में हैं।

"अंकल बोम्मई" के लिये जन-समर्थन के आ ान की जिम्मेदारी किचा को दी गई है- न इससे रत्तीभर ज्यादा और न तिलभर कम। बोम्मई से किये गये प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा, "वे हर उस व्यक्ति के लिये प्रचार करेंगे, जिसके लिये उनसे कहा जायेगा।"

एक प्रश्न के जवाब में किचा ने कहा, "मैं हर उस व्यक्ति के लिये तथा वहाँ प्रचार करूँगा, जिसके लिये या जहाँ के लिये बोम्मई अंकल मुझसे कहेंगे। पर वे यह भी जानते हैं कि मैं हर व्यक्ति के लिये तथा हर जगह प्रचार नहीं कर सकता। (व्यक्ति तथा स्थान का) विस्तृत विवरण अभी तैयार होना है।"

किचा ने कहा, "यह सब पार्टी के लिये नहीं है। यह एक व्यक्ति के लिये हैं, बोम्मई अंकल ने मेरे खराब समय में मेरी मदद की थी। मेरे लिये यह समय उस अहसान को चुकाने का समय है।"

किचा के बारे में बोम्मई ने कहा, "यह लम्बे समय से मेरे निजी तथा पारिवारिक मित्र हैं। मैंने इनसे प्रचार के लिये अनुरोध किया तथा इसके लिये राजी हो गये हैं। वे इस प्रश्न से खीजे हुये नजर आये कि क्या फिल्म स्टारों से प्रचार कराना इस बात का संकेत है कि भाजपा कमजोर स्थिति में है। उन्होंने झल्लाते हुये पलटवार किया, "कांग्रेस में कई स्टार हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस हार रही है?"

प्रसंगवश बता दें कि भाजपा दक्षिण भारतीय राज्यों के फिल्म, खेल तथा मनोरंजन-जगत के सुपर स्टारों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है तथा इस संदर्भ में प्रधानमंत्री दक्षिण के अपने दौरों के दौरान ऐसी अधिकतम सम्भव सेलिब्रिटिज से भेंट भी कर रहे हैं। कर्नाटक में, प्रधानमंत्री अपने पूर्व प्रवासों के दौरान राज्य की फिल्मी हस्तियों, जैसे यश, ऋषभ शेट्टी, प्रशांत नील, विजय किरगन्दुर तथा खेल सितारों जैसे पूर्व क्रिकेटरों अनिल कुम्बले, जवागल श्रीनाथ, वैंकटेश प्रसाद तथा मयंक अग्रवाल के साथ मीटिंग कर चुके हैं।

'राहुल गांधी में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को प्रभावित नहीं कर सकता है। उन्होने कहा कि इस तरह से कांग्रेस काम करती है पर जो हुआ उसके जिम्मेदार वे खुद भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा कि वे मोदी की विचारधारा से सहमत नहीं है पर वे जितनी मेहनत करते हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होने इस बात से इंकार किया कि वे "मोडिफाइड" हो गए हैं, उन्होने कहा कि असल में वे "आज़ादिफाइड" हो गए हैं।

गुलाम नबी ने जम्मु और कश्मीर के संदर्भ में माना कि ना तो मोदी अछूत है और ना भाजपा।

सब कुछ हालात पर निर्भर करता है कि चुनाव में किस को कितनी सीटें मिलती हैं। पूर्व सदर-ए-रियासत डॉ. करण सिंह ने पुस्तक का विमोचन किया और अपने मित्र गुलाम नबी की तारीफ भी की।

इस अवसर पर डॉ. करण सिंह, डॉ. फारुख अब्दुल्लाह, अभिनेता संजय खान, कांग्रेस पार्टी में जनार्दन द्विवेदी और आनंद शर्मा, एन.सी.पी. से प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले, द्रमुक से कनिमाई और शिव मौजूद थे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, के.सी. त्यागी, प्रियंका चतुर्वेदी व अन्य नेता तथा मीडिया की प्रमुख हस्तियां भी मौजूद थीं।

फ्रांस के राष्ट्रपति की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ मेलजोल बढ़ाते रहे हैं।

यूक्रेन में रूस के आक्रमण से ठीक पहले चीन और रूस ने अपने-अपने राष्ट्रपतियों के माध्यम से अपनी "अगाध" मित्रता की घोषणा की थी। दोनों नेता इसे अनेक बार दोहरा चुके हैं। यद्यपि, ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के चीन दौरे का वास्तविक उद्देश्य फ्रांस के कारोबार को गति प्रदान करना है। फ्रांस को उम्मीद है कि वह अपने यहां निर्मित लड़ाकू विमानों को बड़ी संख्या में चीन को निर्यात करेगा। चीन से और आर्डर्स प्राप्त करने की संभावनाओं को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वहां की विभिन्न कम्पनियों के 50 मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बिजनैसमैन चीन दौरे पर हैं।

उनके चीन दौरे ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जूझ रहे यूक्रेन के पक्ष में यूरोपीय देशों की कथित एकजुटता को गलत साबित कर दिया है। वास्तव में यूरोपियन यूनियन ने कई सदस्य देशों ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियारों की सप्लायी की है।

चीन यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करता रहा है।

यूक्रेन के लिए रूस की चुनौती का सामना करने में पश्चिमी देशों की एकजुटता ही उसका प्रमुख संबंध रहा है। फ्रांस ने अपने स्वयं के आर्थिक हितों के मद्देनज़र अब चीन के साथ संबंध पुन: स्थापित करने के एकतरफा प्रयास शुरू कर दिए हैं।

नि:संदेह, फ्रांस का कदम यूक्रेन के क्षेत्रों पर कब्जा करने के रूस के इरादों को मजबूती प्रदान करेगा। रूस अपने एजेण्डे को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप के देशों में इसी तरह के विभाजन की राह देखता रहा है।

दूसरी ओर चीन के लिए विपक्षी खेमे के फ्रांस का रूस उसके स्वयं के उत्कर्ष के समान है। चीन ने रूस के साम्राज्यवादी विस्तार की तर्ज पर ही अपने वर्तमान क्षेत्र का और आगे विस्तार का एजेण्डा तय किया है।

चीन ने, उदाहरण के तौर पर भारत के अरूणाचल प्रदेश के 11 स्थलों के नाम परिवर्तन किए हैं और वह इन्हें अपना बताने का दावा कर रहा है। इससे पूर्व भी उसने भारत की जगहों का नाम बदलने की ट्रिक अपनाई और यह बताने के लिए इसे बतौर साक्ष्य प्रयुक्त किया कि ये क्षेत्र चीन के हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिन्दम बागची ने एक प्रैस बयान में कहा कि चीन द्वारा नाम परिवर्तित करना जमीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता।

अरूणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और भविष्य में भी रहेगा।

चीन को यूक्रेन में शांति का मध्यस्थ बताकर फ्रांस केवल उसके अहंकार को बढ़ा रहा है और मैक्रॉं के दौरे के बाद अंतिम परिणामों में शायद ही कोई बदलाव हो।

'चीन के साथ टकराव के मुद्दों को साझा करे सरकार'

- **कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, लोकतंत्र में सरकार के अलावा विपक्ष को भी एल.ए.सी. पर देश की वास्तविक परिस्थिति ज्ञात होनी चाहिये।**

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि चीनी घुसपैठ को लेकर स्थिति साफ नहीं है और इस बारे में संसद में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन सरकार चीन से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है इसलिए इस बारे में जानकारी देने के वास्ते सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन के साथ विगत तीन साल से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार सीमा पर विवाद चल रहा है और वास्तविक स्थिति क्या है इसकी किसी को जानकारी नहीं है इसलिए सरकार को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाकर इस बारे में विस्तृत जानकारी विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व को देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर भारत के बहादुर सैनिकों ने डटकर चीनी सेना का मुकाबला किया और उन्हें भारतीय सीमा से भगाया है लेकिन हमारे वीर सैनिकों की शहादत के बावजूद चौंकाने वाली सूचना यह मिली है कि कई सीमावर्ती चौकियों पर भारतीय सैनिकों की गश्त बंद की गई है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि चीन तथा भूटान के बीच सरहद को लेकर बातचीत होने वाली है। भूटान नरेश इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं और वह चीन सीमा के मुद्दे पर भारत को आश्वस्त भी कर रहे हैं लेकिन दोनों मुल्कों के बीच होने वाली वार्ता को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उसे देखकर लगता है कि कहीं कोई ऐसा समझौता नहीं हो जिसका सीधा असर भारत पर पडता हो।

भाजपा ने नयी सोची-समझी रणनीति अपनायी है...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिवार अपनी लोकप्रिय अपील खो चुका है तथा उसे वोट नहीं मिल सकते।

असम के मुख्यमंत्री हिमान्ता बिस्वा सरमा ने एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित एक लेख में राहुल गांधी के खिलाफ क्या-क्या नहीं कहा। उन्होंने इस कांग्रेस नेता की राजनैतिक नैतिकता पर प्रश्न खड़े किये।

पार्टी के पुराने नेताओं द्वारा कांग्रेस तथा राहुल गांधी पर किये जा रहे हमले-दर-हमले सत्तारूढ़ भाजपा की अच्छी तरह सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं क्योंकि जमीनी रिपोर्टों में यह बात सामने आ रही है कि भाजपा नेताओं और मंत्रियों के बयान जनता के गले नहीं उतर रहे हैं।

ऐसी खुफिया सूचनाएं हैं कि कांग्रेस की जमीनी स्तर पर राजनैतिक पकड़ बन रही है तथा राहुल गांधी के लिये आमजन की सहानुभूति भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बात को लेकर विशेष रुप से परेशान हैं कि व्यवसायी गौतम अडानी के बारे में जनता की जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ती जा रही है क्योंकि कांग्रेस प्रधानमंत्री तथा इस व्यवसायी ग्रुप के बीच के संबंधों को लेकर लगातार सवाल कर रही है। अडानी मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा तथा इसके शीर्ष नेता जो चुप्पी धारण किये हुये हैं। उसके बारे में जनता तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कुल मिलाकर यह कहना शुरु कर दिया है कि यह मुद्दा साजिश और कुतूहल से भरा हुआ है।

यही कारण है कि सत्तारूढ़ भाजपा के रणनीति-निर्माताओं ने उन पूर्व कांग्रेसी नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है जो अपनी पूर्व पार्टी पर हमला बोलने में किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। सूत्रों ने कहा है कि रणनीतिकारों की सोच है कि ऐसा करने से जनता का ध्यान अडानी मुद्दे से हट जायेगा।

मानहानि केस में दोष सिद्धि हो जाने के बाद, राहुल गांधी को "विशेष दर्जा" देने के लिये सिधिंया ने कांग्रेस को दोषी ठहराया तथा आरोप लगाया कि पार्टी न्यायपालिका को दबाव में ला रही है तथा प्रासंगिक एवं सुसंगत बने रहने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है।

सिधिंया ने कहा, "इस पार्टी ने पिछड़े वर्गों का अपमान किया, हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी के सबूत माँगे तथा चीन द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई किये जाने की बातें कहीं।" इस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला, जिन पर इस प्रकार के बयानों के आरोप लगाये गये हैं।

सिधिंया ने पत्रकारों से कहा, "कांग्रेस में अब विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं बची है कांग्रेस के पास अब केवल एक ही विचारधारा बची है जो एक देशद्रोही की विचारधरा है, एक ऐसी विचारधारा, जो देश के खिलाफ काम कर रही है।"

सर्वविदित है कि ज्योतिरादित्य सिधिंया लम्बे समय तक कांग्रेस में रहे तथा राहुल गांधी के काफी नजदीक माने जाते थे। उन्होंने नेतृत्व, खासतौर से अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश के पार्टी नेतृत्व से हुये मतभेदों के चलते, 2020 में कांग्रेस छोड़ दी थी तथा भाजपा में शामिल हो गये थे ताकि इसके साथ ही कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी।

मंत्री (सिधिंया) ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की "निजी कानूनी लड़ाई" को लोकतंत्र के लिये लड़ाई के रूप में प्रोजैक्ट कर रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं रख रही है तथा निम्नता की सीमा तक पहुँच रही है। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि वह न्यायपालिका दबाव में लेने तथा उसे डराने की कोशिश कर रही है। इसकी पुष्टि में उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी क्रिमिनल मानहानि केस में अपील करने के लिये सूरत की एक अदालत में गये, तो पार्टी ने वहाँ अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज भेज दी थी।

उन्होंने कहा कि संसद को काम नहीं करने दिया जा रहा तथा उसके नेता काले कपड़े पहनकर संसद में आ रहे है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई नेता डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं।

उन्होंने पूछा कि क्या "गांधीवाद" का दर्शन यही है? एक व्यक्ति के लिये यह सब क्यों किया जा रहा है?

सिधिंया ने कहा कि कांग्रेस के लिये कुछ लोग "प्रथम श्रेणी के नागरिक" है। एक नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि गांधी परिवार पर सामान्य कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं होनी चाहिये।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908